

an>

Title: Need to provide scholarship to the students whose present income is upto rupees one lakh per annum.*

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

पारिवारिक एक लाख रुपये की आय वाले विद्यार्थियों के लिए केन्द्र शासन से राज्य शासन को 100 फीसदी स्कॉलरशिप मिलती है परंतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने विद्यार्थियों को केवल पचास प्रतिशत राशि ही वितरित की जाती है। पचास प्रतिशत स्कॉलरशिप की रकम कहां खर्च होती है, इस बारे में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ब्यौरा लेना चाहिए। वर्ष 2002 से लेकर 2014 तक राज्य सरकार ने करीब 74 लाख विद्यार्थियों के लिए 63 करोड़ 1 लाख 80 हजार 893 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की है परंतु शेष 60 करोड़ रुपये की जो केन्द्र सरकार से राज्य शासन को रकम प्राप्त हुई, उस रकम का क्या हुआ? यह बतई हुई पचास प्रतिशत रकम जो कहीं अन्य काम के लिए खर्च की जाती है, उसका ब्यौरा राज्य शासन से लेना जरूरी है। सरकार को यह ब्यौरा राज्य सरकार से लेना चाहिए। केन्द्र से राज्य सरकार को मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम न मिलने से कम स्कॉलरशिप के कारण लाखों गरीब विद्यार्थियों को भारी नुकसान हो रहा है। चालू शैक्षणिक सत्र में 2015 में स्कॉलरशिप नहीं मिलने से लाखों गरीब विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा देनी भी मुश्किल लग रही है। इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में रखने का काम राज्य सरकार द्वारा होता है। मेरी सरकार से विनती है कि केन्द्र और राज्य सरकार के विवादों में लाखों गरीब विद्यार्थियों का नुकसान न होने पाए, इसका ध्यान सरकार रखे और उनका भविष्य बर्बाद होने से बचाए। तत्काल प्रभाव से स्कॉलरशिप का वितरण गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहिए जिससे विद्यार्थी 2015 की अंतिम परीक्षा दे सकें। धन्यवाद।